पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 1,500 करोड़ रु0 की धनराशि से उ0प्र0 के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल की सब्सिडी वितरण का शुभारम्भ किया

महत्वपूर्ण स्थलों पर अन्नपूर्णा भोजनालय स्थापित किए जाएंगे, शुरुआत मण्डी समितियों से की जाएगी, क्योंकि मण्डियों में बड़ी संख्या में अन्नदाता किसान अपनी उपज लेकर आते : मुख्यमंत्री

निर्धारित टोकन मनी देकर किसान अन्नपूर्णा भोजनालय में भरपेट भोजन प्राप्त कर सकेंगे

अन्नपूर्णा भोजनालयों के माध्यम से श्रमिकों को सस्ते मूल्य पर भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा

निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को काम के दौरान भोजन की चिन्ता न करनी पड़े, इसके लिए यह व्यवस्था विकसित की जा रही

सरकार प्रदेश की महिलाओं के लिए एक विशेष पैकेज लाने जा रही, इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भरता के नए अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा

विगत दिनों भारी बारिश, आंधी और तूफान के कारण प्रभावित किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा तात्कालिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा

सरकार प्रभावित किसानों के लिए अलग से एक विशेष पैकेज लाने जा रही, इससे प्रदेश के लगभग तीन करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे

रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल सब्सिडी केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि प्रदेश की गरीब माताओं और बहनों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता, सम्मान और प्रतिबद्धता का प्रतीक

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 46 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर सामान्य और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हुए

प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, रसोइयों, गांवों में कार्यरत चौकीदारों तथा प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों के मानदेय में वृद्धि की गई

लखनऊ : 03 नवम्बर, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जिन गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, ऐसे 01 करोड़ 89 लाख परिवारों को दीपावली और होली के अवसर पर निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल का उपहार दिया जाएगा। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं,

बल्कि प्रदेश की गरीब माताओं और बहनों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता, सम्मान और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री जी आज यहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 1,500 करोड़ रुपये की धनराशि से उत्तर प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल की सब्सिडी के वितरण के शुभारम्भ कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 10 लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंण्डर रिफिल सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक वितरित किये। कार्यक्रम के दौरान खाद्य एवं रसद विभाग से सम्बन्धित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गयी।

मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क रिफिल गैस सिलेण्डर प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी गरीब परिवार पर्व और त्योहारों की खुशियों से वंचित न रहे। दीपावली का वास्तविक आनंद तभी है, जब समाज का प्रत्येक परिवार उत्साह और उमंग के साथ इस पर्व में सहभागी बने तथा प्रत्येक घर में खुशहाली का वातावरण हो।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 01 मई, 2016 को बलिया से 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' का शुभारम्भ किया था। प्रधानमंत्री जी ने माताओं और बहनों की पीड़ा को भावनात्मक रूप से महसूस करते हुए कहा था कि उनकी आंखों में चूल्हे के धुएं से आने वाले आंसुओं को देखकर सरकार चुप नहीं रह सकती। इसी संवेदना के साथ गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि गरीबों को गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए रिश्वत और अनावश्यक खर्च न करना पड़े।

घरेलू रसोई गैस के एक सिलेण्डर की कीमत 983.45 रुपये है। इसमें भारत सरकार की ओर से 335.40 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस प्रकार लाभार्थी को एक भरे हुए सिलेण्डर के लिए अपनी ओर से 648.55 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। राज्य सरकार ने दीपावली से पहले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की ओर से देय पूरी धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कम्पनी को कर दिया है। अब लाभार्थी अपनी गैस एजेन्सी पर जाकर सिलेण्डर प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रत्येक लाभार्थी परिवार को लगभग 650 रुपये की बचत होगी। इस बचत से गरीब परिवार दीपावली के लिए मिठाई खरीद सकेंगे, घर में दीपक जला सकेंगे और अपने बच्चों के साथ त्योहार की खुशियां मना सकेंगे। सरकार की यह पहल गरीब परिवारों की दीपावली को और अधिक उल्लासपूर्ण एवं प्रकाशमय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो वह अच्छे कार्य करती है। पहले गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लोगों को कनेक्शन के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे

और भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता था। गरीब परिवारों की महिलाएं लकड़ी एवं अन्य पारम्परिक ईंधन से चूल्हे पर खाना बनाने को विवश थीं। प्रधानमंत्री जी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था प्रारम्भ की। यही सुशासन है, जहां शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक बिना भेदभाव, बिना बिचौलिये और बिना भ्रष्टाचार पहुंचे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत सप्ताह आयी विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत में आए व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 46 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर सामान्य और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हुए हैं। वर्ष 2014 के पूर्व और उसके बाद देश के हालात की तुलना करने पर परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। वर्ष 2014 से पूर्व युवा बेरोजगारी से परेशान थे, किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे तथा गरीब परिवारों के सामने भूख और जीवनयापन का संकट था। लोगों के हाथों को काम नहीं मिलता था और महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के लिए पर्याप्त योजनाएं एवं अवसर उपलब्ध नहीं थे।

वर्ष 2014 के पश्चात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और घोटालों पर प्रभावी रोक लगी। जनता का विश्वास मजबूत हुआ और देश विकास तथा सुशासन के नए मार्ग पर आगे बढ़ा। इसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी और प्रदेश को विकास, सुरक्षा तथा सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर मिला।

वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में पर्व और त्योहारों के समय लोगों को अपनी सुरक्षा तथा सम्पत्ति की चिन्ता सताती थी। त्योहार आने से पूर्व ही उपद्रव और अराजकता की घटनाएं शुरू हो जाती थीं। दंगे और कर्फ्यू आम थे। बेटियां तथा व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। आम नागरिक भय के वातावरण में जीवन जीने को मजबूर था।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आजकल दीपावली का समय है। बाजारों में रौनक व चहल–पहल दिखाई दे रही है। यह उत्साह प्रमाण है कि प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बना है। आज कोई बेटी या बहन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब कोई अपराधी किसी व्यापारी से जबरन वसूली नहीं कर सकता और न ही कोई व्यक्ति दंगा करने का दुस्साहस कर सकता है। प्रदेश में कानून–व्यवस्था की ऐसी स्थिति बनाई गई है कि कर्फ्यू लगाने की नौबत ही न आए। सरकार का प्रयास है कि इस उत्साह और खुशहाली में गरीब परिवार भी समान रूप से सहभागी बनें। पहले निःशुल्क गैस कनेक्शन और अब निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल की सुविधा इसी सोच का परिणाम है। पर्व और त्योहारों की खुशी तभी सार्थक है, जब समाज का प्रत्येक परिवार इससे जुड़ा हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनके आर्थिक सशक्तीकरण

के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की परिस्थितियों में तेजी से बदलाव हो रहा है। असमय चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में किसानों की फसलें प्रभावित होती हैं और उनकी मेहनत तथा लागत पर संकट खड़ा हो जाता है।

विगत 15 दिनों में दो बार भारी बारिश, आंधी और तूफान के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरकार ने इस नुकसान को गम्भीरता से लेते हुए किसानों को तत्काल राहत देने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा तात्कालिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार किसानों के लिए अलग से एक विशेष पैकेज लाने जा रही है। इस पैकेज से प्रदेश के लगभग तीन करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे।

अन्नदाता किसान के परिश्रम का सम्मान करना और संकट की घड़ी में उसके साथ खड़ा होना सरकार की प्राथमिकता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को होने वाली क्षति की भरपाई के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी। किसानों को राहत देने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को सुरक्षित बनाने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

डबल इंजन सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ उनकी गरिमा, सम्मान और आर्थिक स्वावलम्बन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया है। अब उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में प्रयासों को और तेज किया जाएगा। सरकार प्रदेश की महिलाओं के लिए एक विशेष पैकेज लाने जा रही है। इस पैकेज के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भरता के नए अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक महिला आत्मनिर्भर हो, अपने परिवार की ताकत बने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी तो उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर व विकसित होगा। उत्तर प्रदेश के विकसित होने से भारत के विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग और अधिक प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प लिया है, उसकी पूर्ति के लिए प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी महोत्सव का वर्ष होगा। वह समय भारत प्रत्येक नागरिक के लिए खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक बने, इसके लिए अभी से व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाएं इसी व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेण्डर उपलब्ध कराना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। इसके बाद अन्य कार्यक्रमों की श्रृंखला भी प्रारम्भ होने जा रही है। प्रदेश की सभी माताएं और बहनें स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें और यह तय करें कि वह किस प्रकार का कार्य प्रारम्भ करना चाहती हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेगी। ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसे महिलाएं अपनी इच्छाशक्ति, परिश्रम और सरकार के सहयोग से सफलतापूर्वक पूरा न कर सकें।

पहले महिलाएं सूर्यास्त के उपरान्त घर से बाहर निकलने में डरती थीं, लेकिन आज उद्योगों में रात्रिकालीन पाली में भी काम कर रही हैं। अब उनके समक्ष सुरक्षा को लेकर आशंकाएं नहीं हैं। प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाया गया है, जहां महिलाएं अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य कर सकती हैं तथा आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा सकती हैं। प्रदेश में लखपति दीदी और बी0सी0 सखी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

राशन की दुकानों के उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि की गई है। इन दुकानों को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के लिए मॉडल शॉप तथा अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऐसे अन्नपूर्णा भवन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे राशन वितरण व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हो तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके।

प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, रसोइयों, गांवों में कार्यरत चौकीदारों तथा प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों के मानदेय में वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, अन्य वर्गों के मानदेय में वृद्धि करने की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक खुशहाली पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम के अनुरूप सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं की एक और महत्वपूर्ण श्रृंखला आगे बढ़ाने जा रही है। इसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण स्थलों पर अन्नपूर्णा भोजनालय स्थापित किए जाएंगे। इन भोजनालयों की शुरुआत मण्डी समितियों से की जाएगी, क्योंकि मण्डियों में बड़ी संख्या में अन्नदाता किसान अपनी उपज लेकर आते हैं। कई बार किसानों को लम्बे समय तक वहां रुकना पड़ता है। ऐसे में उसके भोजन की व्यवस्था भी सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले मण्डी आने वाला किसान गुड़ और पानी के सहारे काम चलाने को मजबूर होता था, लेकिन अब यदि उसे दो रोटी खाने की आवश्यकता है तो वह निर्धारित टोकन मनी देकर अन्नपूर्णा भोजनालय में भरपेट भोजन प्राप्त कर सकेगा। सरकार का प्रयास है कि किसान को केवल उसकी उपज का उचित मूल्य ही न मिले, बल्कि मण्डियों में आने–जाने के दौरान उसकी मूलभूत आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए। अन्नपूर्णा भोजनालय किसानों के सम्मान और सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होंगे।

पहले श्रमिकों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था। आज सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक कार्य कर रही है। श्रमिकों के बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। बच्चों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने के अवसर तथा बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि श्रमिक का बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को पूरा कर सके और जीवन में आगे बढ़े।

श्रमिकों की सुविधा के लिए लेबर अड्डे भी बनाए जा रहे हैं। इन लेबर अड्डों पर श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। अन्नपूर्णा भोजनालयों के माध्यम से श्रमिकों को सस्ते मूल्य पर भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को काम के दौरान भोजन की चिन्ता न करनी पड़े, इसके लिए यह व्यवस्था विकसित की जा रही है। किसान, श्रमिक और समाज के कमजोर वर्गों को यह महसूस होना चाहिए कि वह भी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सरकार उनकी आवश्यकताओं, सुरक्षा तथा सम्मान का पूरा ध्यान रख रही है। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मिले, प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा हो और प्रत्येक नागरिक को स्वावलम्बन के पथ पर आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, यही सरकार की कार्यशैली और जनकल्याणकारी योजनाओं का मूल उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गरीब परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीबों के घरों में निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा है। बिजली की व्यवस्था है। सड़कें बनाई जा रही हैं। पेयजल की व्यवस्था घरों तक पहुंचाई जा रही है। उपचार के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के कार्य किए जा रहे हैं। जब गरीब परिवारों को गैस, बिजली, सड़क, पेयजल, उपचार और आवास जैसी सुविधाएं मिलेंगी तथा युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, तभी समाज में वास्तविक खुशहाली आएगी।

सरकार प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योजनाओं की श्रृंखला संचालित कर रही है। कोई भी वर्ग ऐसा न हो, जो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहे। सरकार की प्रत्येक योजना के पीछे भावना है कि प्रत्येक नागरिक को खुशहाल बनाया जाए। उसे सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन का अवसर मिले।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों की माताओं–बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाकर उनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री जी ने दीपावली और होली पर निःशुल्क गैस सिलेण्डर रिफिल की व्यवस्था कर गरीब परिवारों को अतिरिक्त राहत दी है। प्रदेश सरकार गरीबों को निःशुल्क राशन, आवास, शौचालय, बिजली, सड़क और आयुष्मान योजना के माध्यम से पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून–व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है तथा उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर रेवेन्यु सरप्लस स्टेट बना है।

खाद्य एवं रसद मंत्री श्री मनोज पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खाद्य एवं रसद विभाग की योजनाओं में पारदर्शिता आयी है और पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंच रहा है। लगभग 14 करोड़ 65 लाख लोगों को निःशुल्क राशन वितरण, अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण, उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को राशन दुकानों के संचालन से जोड़ना इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं।

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बिना भेदभाव जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य डॉ0 लालजी प्रसाद निर्मल, श्री श्रीराम चन्द्र प्रधान, विधायक श्री योगेश शुक्ला, श्री ओ0पी0 श्रीवास्तव, श्रीमती जय देवी, श्री अमरेश कुमार, महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल, सलाहकार मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

————————

PN-CM-Ujjwala Free LPG Cylinder Distribution Programme-03 November, 2026